

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— पीयूष समारिया  
आई०ए०एस०



राजस्व अपील सं० 18/2019

1. रज्जो पत्नि हारया जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।

... अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 29.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रज्जो मु०नं० 199/2018 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलांत  
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 03.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा जिला दौसा ने दिनांक 29.10.2018 को ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा के खसरा नं० 306 रकबा 0.10 है० किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को विधिवत तामील करवाये बिना व सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना पीठ पीछे से निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके की जाँच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

h

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं0 306 रकबा 0.10 है0 किस्म चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्तकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। बेदखली एवं फसल जब्ती व नीलामी की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2018 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयूष सेमारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष सेमारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा

